

कथति लव जहिाद और भूमिजहिाद पर सरकार की कार्रवाई

चर्चा में क्यों

हाल ही में उत्तराखण्ड सरकार ने राज्य में [जनसांख्यिकीय परिवर्तन](#) पर बढ़ती चर्चाओं के बीच [लव जहिाद](#), [भूमिजहिाद](#) और [ज़बरन धर्मांतरण](#) के वरिुद्ध कार्रवाई शुरू की है।

मुख्य बरिु

- जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर चर्चा व्यक्त की गई, विशेष रूप से [पुरुला](#), [धारचूला](#) और [नंदनगर](#) जैसे क्षेत्रों में।
- [उत्तराखण्ड की जनसंख्या](#): लगभग 11.1 मिलियन, जिसमें [हिंदू धरुम](#) प्रमुख धरुम (82.97%) है, उसके बाद इस्लाम (13.95%) और ईसाई धरुम (0.37%) हैं, जैसा कि [2011 की जनगणना](#) तथा 2023 के अनुमानों द्वारा पता चलता है
 - जबकि राज्य में शहरी प्रवास और विकास हो रहा है, जनसांख्यिकीय परिवर्तनों को लेकर चर्चाओं ने तनाव बढ़ा दिया है, विशेष रूप से धारुमिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में।
- [उत्तराखण्ड धारुमिक स्वतंत्रता अधनियम, 2018](#)
 - इस कानून के तहत धरुम परिवर्तन करने वाले लोगों को यह घोषति करना आवश्यक है कि उनका धरुम परिवर्तन ज़ोर जबरदस्ती, दबाव या धोखाधड़ी के माध्यम से नहीं किया गया है
 - यह प्राधिकारियों को उन वरिाहों को अमान्य घोषति करने का अधिकार भी देता है, जो केवल लड़की को एक धरुम से दूसरे धरुम में परिवर्तित करने के लिये किये गए हों।
 - [कड़े प्रावधान](#): यह अधनियम गैरकानूनी धारुमिक रूपांतरण को संजज्ञेय और गैर-ज़मानती अपराध बनाता है तथा बल, लालच या धोखाधड़ी के माध्यम से धर्मांतरण को अपराध मानता है।
 - [अधिक सज़ा](#): अवैध धरुम परिवर्तन के लिये अपराधियों को न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष तक की जेल की सज़ा हो सकती है।
 - [उच्च जुरमाना](#): 50,000 रुपए का अनवरिय जुरमाना लगाया जाता है तथा संभावति रूप से अपराधी को पीड़ति को मुआवज़े के रूप में 5 लाख रुपए तक का भुगतान करना पड़ता है।